NYCS
RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com
जनवरी 2026, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 से

सशक्त हुई भारतीय सहकारिता

अंदर के पन्नों पर

अन्न भंडारण योजना के लिए मिली छूट
कैंपस कोऑपरेटिव से युवाओं में बढ़ेगी जागरूकता

International Year of Cooperatives 2025

Cooperatives Build a Better World

KRIBHCO

Cooperative and beyond...

SERVING **FARMERS** **TO GROW** BOUNTIFUL

KRIBHCO world's premier fertilizer producing cooperative has been consistently making sustained efforts towards promoting modern agriculture and cooperatives in the country. It helps farmers maximize their returns through specialised agricultural inputs and other diversified businesses.

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD

Registered Office: A-60, Kailash Colony, New Delhi-110048 | **Phone: 011-29243412**

Corporate Office: KRIBCHO BHAWAN, A 8-10, Sector-1, Noida-201301, Distt: Gautam Budh Nagar (UP) | **Phones:** 0120-2534631/32/36

Website: www.kribhco.net | **KRIBCHO Kisan Helpline:** 0120-2535628 | **E-mail:** krishipramarsh@kribhco.net

OUR PRODUCTS

Neem Coated Urea | DAP | MOP | NPK | NPS | MAP | Liquid Bio Fertilizers | Certified Seeds | Hybrid Seeds
City Compost | Zinc Sulphate | Natural Potash | Sivarika | Rhizosuper

युवा सहकार

वर्ष : 02, अंक-07, जनवरी-2026

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता
दर्शन सोलंकी (विशेष आमंत्रित)
देवेन्द्र सिंह (विशेष आमंत्रित)
रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी (सीईओ)

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं मित्तल प्रिंट एन पैक, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

अंतरराष्ट्रीय वर्ष से भारतीय सहकारिता ने जमाई धाक 04
हर दशक में मनेगा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 05

06
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 से सशक्त हुई भारतीय सहकारिता

16
कैंपस कोऑपरेटिव से युवाओं में बढ़ेगी जागरूकता

कृषि, पशुपालन और सहकारिता के संगम से ग्रामीण हो रहे समृद्ध 12
अन्न भंडारण योजना के लिए मिली छूट 14
सहकारिता सुधारों पर राष्ट्रीय विमर्श 18
AI से एक साल में लैस होंगे 10 लाख युवा 20
पुस्तकों, विचारों और संस्कृति का जन-उत्सव 22
युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही एनवाईसीएस 24
एनवाईसीएस के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 26
विलक्षण वैभव सूर्यवंशी 28
दिल्ली-एनसीआर में शुरू हुई भारत टैक्सी 30

अंतरराष्ट्रीय वर्ष से भारतीय सहकारिता ने जमाई धाक

‘सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं’ के थीम पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का समापन हो गया। भारतीय सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने और इसका उज्ज्वल भविष्य तय करने में इस वर्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान के रूप में सहकारी मॉडल को बढ़ावा देना था। इसका औपचारिक समापन अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के नवंबर 2025 में कतर की राजधानी दोहा में आयोजित वैश्विक सहकारी सम्मेलन में किया गया।

संयुक्त राष्ट्र ने अब तय किया है कि हर 10 वर्ष में एक वर्ष को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय ऐसे दौर में आया है जब दुनिया पर्यावरणीय संकट, बढ़ती असमानता और संस्थाओं में घटते भरोसे का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र बहुत कम ही किसी विषय को बार-बार अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मान्यता देता है।

सहकारिताएं समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास में लंबे समय से अहम और परिवर्तनकारी भूमिका निभाती आ रही हैं। यह लोगों को आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में अधिकतम भागीदारी का अवसर देती हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी इनकी भूमिका अहम है। लोकतांत्रिक स्वामित्व और समुदाय के हित को प्राथमिकता देने के कारण सहकारिताएं ऐसे विकास का मॉडल प्रस्तुत करती हैं जो समावेशी होने के साथ-साथ टिकाऊ भी है। इससे पहले 2012 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया गया था। इन वर्षों का भारत सहित वैश्विक स्तर पर सकारात्मक असर देखने को मिला। इसी अनुभव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने अब तय किया है कि हर 10 वर्ष में एक वर्ष को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय ऐसे दौर में आया है जब दुनिया पर्यावरणीय संकट, बढ़ती असमानता और संस्थाओं में घटते भरोसे का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र बहुत कम ही किसी विषय को बार-बार अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मान्यता देता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस वर्ष के दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं उनसे भारतीय सहकारिता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, राज्य सरकारों के सहकारिता विभाग सहित विभिन्न सहकारी संस्थाओं ने देशव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरुक किया है। इसका असर यह हुआ कि अब घर-घर में सहकारिता की चर्चा होने लगी है। सहकारी क्षेत्र के विकास एवं विस्तार के लिए सहकारिता मंत्रालय की 100 से अधिक प्रभावी पहलों के माध्यम से सहकारिता ने आज गांवों की आर्थिक आत्मनिर्भरता और किसानों की समृद्धि के द्वार खोल दिया है। इससे तकरीबन 30 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली भारतीय सहकारिता की जड़ें और मजबूत हुई हैं।

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) ने भी इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। दिसंबर 2025 में समर्थ युवा फाउंडेशन के सहयोग से ‘सतत विकास के लिए सहकारिता’ विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक विकास, स्थिरता तथा कौशल विकास में सहकारिता की भूमिका पर गहन चर्चा करना एवं सहकारी आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाना था। 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें सहकारिता क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण होगा। सरकार की विभिन्न पहलों से अगले कुछ वर्षों में भारत इंजन के रूप में वैश्विक सहकारिता आंदोलन को गति देगा। इस यात्रा में एनवाईसीएस की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

हर दशक में मनेगा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

युवा सहकार टीम

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सहकारिताओं की भूमिका को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। महासभा ने औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया है कि सहकारिताएं समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास में लंबे समय से अहम और परिवर्तनकारी भूमिका निभाती आ रही हैं। इसी के साथ यह निर्णय भी लिया गया है कि अब हर 10 साल में एक अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया जाएगा।

यह प्रस्ताव सामाजिक विकास में सहकारिताएं शीर्षक से 15 दिसंबर, 2025 को अपनाया गया था और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक दस्तावेज मंच पर प्रकाशित हुआ है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया असमानता, जलवायु संकट और सामाजिक विभाजन जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने माना कि 2012 और 2025 में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्षों का वैश्विक स्तर पर सकारात्मक असर देखने को मिला। इसे देखते हुए ही यह तय किया गया है कि सरकारों, संस्थानों और समाज को सहकारिता को सतत विकास के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाने के लिए हर दशक में एक वर्ष को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में समर्पित किया जाएगा।

प्रस्ताव में कहा गया है कि सहकारी समितियां लोगों को आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में अधिकतम भागीदारी का अवसर देती हैं। ये संस्थाएं गरीबी और भूख मिटाने, खाद्य सुरक्षा मजबूत करने, सामाजिक समावेशन बढ़ाने, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन में प्रत्यक्ष योगदान देती हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहकारी समितियों की भूमिका को अहम माना गया है। लोकतांत्रिक स्वामित्व और समुदाय के हित को प्राथमिकता देने के कारण सहकारिताएं ऐसे विकास का मॉडल प्रस्तुत करती हैं जो समावेशी होने के साथ-साथ टिकाऊ भी है।

इस प्रस्ताव में सहकारी गतिविधियों को सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ा गया है। इसमें आदिवासी समुदायों, ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहकारिताओं की भूमिका को स्वीकार किया गया है। कृषि, वित्त, आवास और सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सहकारिताएं जमीनी स्तर पर विकास की खाई को पाटने का काम कर रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों से यह भी आग्रह किया है कि वे सहकारिताओं के लिए अनुकूल नीतिगत और संस्थागत माहौल तैयार करें। इसमें बेहतर कानूनी और नियामकीय ढांचा, पूंजी तक आसान पहुंच, निष्पक्ष टैक्स व्यवस्था, कृषि और वित्तीय सहकारिताओं को समर्थन, डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार, शोध और आंकड़ों को मजबूत करना तथा सहकारिताओं में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना शामिल है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस को हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाने की परंपरा को भी दोहराया गया है। वर्ष 2026 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसकी थीम बाद में घोषित की जाएगी।

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) के अध्यक्ष डॉ. एरियल गुआर्को ने संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले पर कहा कि यह निर्णय ऐसे दौर में आया है जब दुनिया पर्यावरणीय संकट, बढ़ती असमानता और संस्थाओं में घटते भरोसे का सामना कर रही है। सहकारिताएं यह साबित करती हैं कि बिना किसी को पीछे छोड़े संपत्ति का निर्माण और वितरण संभव है। साथ ही पर्यावरण और सामाजिक रिश्तों की भी रक्षा की जा सकती है। आईसीए के महानिदेशक जेरोन डगलस ने इसे एक असाधारण फैसला बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र बहुत कम किसी विषय को बार-बार अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मान्यता देता है।

संयुक्त राष्ट्र का यह फैसला वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए एक नई ऊर्जा और दिशा देने वाला माना जा रहा है, जिससे सहकारिताएं आने वाले वर्षों में समावेशी और न्यायपूर्ण विकास की मजबूत धुरी बन सकेंगी।■

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 से

सशक्त हुई भारतीय सहकारिता

संयुक्त राष्ट्र के पहल से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मिली नई अंतरराष्ट्रीय पहचान और भविष्य की दिशा

वैश्विक स्तर पर बुलंद हुई भारतीय सहकारिता की आवाज, घरेलू स्तर पर लोगों में बढ़ी जागरूकता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारिता की भूमिका हुई मजबूत

देश में पहली बार बनी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एवं नमक कोऑपरेटिव, नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी हुई लागू

अभिषेक राजा

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के समापन के साथ ही वैश्विक सहकारिता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। यह भारत के लिए गतिशील प्रगति, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक नया दौर है। सामाजिक विकास और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारिता की सशक्त भूमिका को मान्यता देने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 'सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है' विषय के तहत मनाए गए इस वर्ष ने गरीबी से लड़ने, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और सतत आर्थिक विकास को गति देने के लिए समुदाय संचालित व्यावसायिक मॉडलों की पूरी क्षमता के उपयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से जो कदम उठाए गए और राज्यों के स्तर पर जिन कार्यक्रमों, अभियानों और पहलों का आयोजन किया गया उससे न सिर्फ सहकारिता को लेकर जागरूकता बढ़ी, बल्कि भारतीय सहकारिता आंदोलन को नई अंतरराष्ट्रीय पहचान और दिशा मिली है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान सहकारिता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और सहकारी संगठनों द्वारा लोगो और डाक टिकट का उपयोग किया। इसमें राज्यों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं उनसे भारतीय सहकारिता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है। देश में पहली बार त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का गठन हो, नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का गठन हो, देश में पहली बार नमक कोऑपरेटिव की शुरुआत हो, दुग्ध क्रांति 2.0 की शुरुआत हो, डेयरी सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी को बढ़ावा देने के लिए तीन नई कोऑपरेटिव बनाने और सहकार टैक्सी शुरू करने की घोषणा सहित अन्य दर्जनों पहल से भारतीय सहकारिता ने नई उड़ान भरी है। इनसे सहकारिता का भविष्य उज्ज्वल बनाने में भी मदद मिलेगी।

वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने के संयुक्त राष्ट्र के निर्णय में भारत की अहम भूमिका रही। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय सहकारिता की आवाज बुलंद हुई। दुनिया की करीब एक चौथाई सहकारी संस्थाओं वाली भारतीय सहकारिता की आवाज को अब गंभीरता से लिया जाने लगा है। इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का औपचारिक उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया और दुनिया की सहकारी संस्थाओं के शीर्ष संगठन अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) ने पहली बार भारत में अपनी महासभा और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय सहकारिता की धमक महसूस की गई। आईसीए विश्व भर में सहकारी समितियों की आवाज के रूप में कार्य करता है। यह संवाद, क्षमता निर्माण और वकालत के लिए सहकारी समितियों को वैश्विक मंच प्रदान करता है और एक निष्पक्ष एवं न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सहकारी समितियों के महत्व का समर्थन करता है। इसका मिशन सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक निर्णय लेने और सतत सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के स्थायी सिद्धांतों पर आधारित है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और राज्य सरकारों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के कोने-कोने में आयोजित सहकारिता सम्मेलनों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान सहकारिता की अलख जगाने वालों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और सहकारिता के मंत्र की महिमा के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गरीबी, कुपोषण और बेघर लोगों के हितों का ध्यान सहकारिता के माध्यम से रखा जा सकता है। किसानों को उनकी खेती की जरूरत के सभी इनपुट और उपज की खरीद में सहकारिता की भूमिका का महत्व भी उन्होंने समझाया।

भारत में सहकारिता प्राचीन समय से ही जन-जीवन का आधार रहा है। हमारे कृषि प्रधान समाज में तो यह रोजमर्रा के कामकाज का एक अभिन्न हिस्सा है। 121 वर्ष पहले 1904 में संगठित रूप से सहकारिता की शुरुआत के बाद इसे आधुनिक और प्रभावी दिशा वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मिली। सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के बाद से सहकारी मूल्य श्रृंखला की हर कड़ी को मजबूत करने के उद्देश्य से 100 से अधिक परिवर्तनकारी पहल शुरू की हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्रालय सहकारी समितियों को गतिशील, जन-केंद्रित उद्यमों में विकसित होने में सक्षम बना रहा

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की प्रमुख पहल

- अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल के नाम पर देश में पहली बार स्थापित हुई कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी
- सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई सहकारिता नीति 2025 हुई लागू
- कच्छ के नमक उत्पादकों के लिए देश में पहली बार बनी नमक कोऑपरेटिव
- सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव
- दुग्ध क्रांति 2.0 की हुई शुरुआत, डेयरी सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी को बढ़ावा देने के लिए तीन नई नेशनल कोऑपरेटिव बनाने की घोषणा
- परिवहन क्षेत्र में सहकारिता को मजबूत करने के लिए पहली बार शुरू की गई सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी
- कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बैंक में हुआ तब्दील, ग्रामीण सहकारी बैंकों के फेडरेशन के रूप में करेगा काम
- देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता क्षेत्र की हिस्सेदारी का पता लगाने के लिए गठित हुई जीडीपी कमेटी
- पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत पूरे देश में लगाए गए करोड़ों पेड़-पौधे

सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2025 भारत और विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े सहकारी पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है जिसने यह दिखाया है कि सहकार कैसे समावेशी और टिकाऊ विकास को गति दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष ने वैश्विक सहकारी दृष्टिकोण को आकार देने में भारत के नेतृत्व को पुनः स्थापित किया।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

है जो सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान देशभर में आयोजित सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों, अभियानों एवं पहलों पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट भारत के सहकारी संस्थानों की सामूहिक उपलब्धियों को दर्शाती है। इसमें उन अभियानों, नवाचारों और ज्ञान साझाकरण प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया है जो मिलकर एक सहकारी, टिकाऊ और न्यायसंगत दुनिया को आकार देने में भारत के नेतृत्व को उजागर करते हैं।

प्रधानमंत्री बोले, भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण

इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, 'सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2025 भारत और विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े सहकारी पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है जिसने यह दिखाया है कि सहकार कैसे समावेशी और टिकाऊ विकास को गति दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष ने वैश्विक सहकारी दृष्टिकोण को आकार देने में भारत के नेतृत्व को पुनः स्थापित किया। इस वर्ष के दौरान विभिन्न हितधारकों ने सहकारी समितियों के दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रचार गतिविधियां, क्षमता निर्माण प्रयास और सामुदायिक पहल की हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आयोजन न केवल भारत की समृद्ध सहकारी विरासत का उत्सव है, बल्कि सहकारिता के माध्यम से वैश्विक एकजुटता को मजबूत करने का आह्वान भी है। 'सहकार से समृद्धि' के शाश्वत मूल्यों से प्रेरित होकर भारत का सहकारी आंदोलन 2047 तक विकसित भारत और विश्वास, सहयोग और साझा समृद्धि पर आधारित विश्व की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहा है।'

परिवर्तन का नया युग

इसी रिपोर्ट में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा, 'भारत में सहकारिता आंदोलन परिवर्तन के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसा युग जो नवाचार, समावेशिता और राष्ट्र की समृद्धि को गति देने के सामूहिक संकल्प द्वारा परिभाषित है। भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इसे नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित आईसीए के वैश्विक सहकारी सम्मेलन और महासभा में आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई अग्रणी पहलों जैसे कि एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल ने भारत

के सहकारी क्षेत्र को विस्तार दिया है। ये संगठन भारतीय किसानों को वैश्विक बाजारों से जुड़ने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने और अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बना रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों को भी वैश्विक अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली ये पहलें इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि सहकारी शक्ति किस प्रकार स्थानीय क्षमता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सफलता में बदल सकती है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कुशल और भविष्य के लिए तैयार सहकारी कार्यबल के पोषण हेतु नेतृत्व विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देती है।'

जागरूकता को बढ़ावा

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का मुख्य लक्ष्य सतत विकास और गरीबी उन्मूलन पर सहकारी समितियों के स्थायी प्रभाव के बारे में विश्वव्यापी जन जागरूकता बढ़ाना था। इसमें उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देकर सहकारी विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, वैश्विक स्तर पर सहायक कानूनी और नीतिगत ढांचों की वकालत करना और युवाओं की भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए सार्थक नेतृत्व को प्रेरित करना शामिल था। पूरे वर्ष के दौरान सहकारी समितियों और सहायक संस्थानों ने शिक्षा, जनसंपर्क, सहयोगात्मक साझेदारी और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से इन लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत गतिविधियों का दायरा व्यापक और बहुआयामी था, जिसमें जागरूकता अभियान, कौशल विकास कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और नीतिगत संवाद शामिल रहे। इन सामूहिक प्रयासों से सरकारी संस्थानों, सहकारी संघों, विकास एजेंसियों और आम जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिली जिससे सहकारी क्षेत्र की परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में क्षमता को बल मिला। केंद्र,

आईवाईसी 2025 की प्रमुख गतिविधियां

- राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम
- जागरूकता अभियान और आउटरीच गतिविधियां
- कार्यशालाएं, सेमिनार और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- पैदल मार्च, रैलियां और अन्य जन भागीदारी अभियान
- नई पहलों और कार्यक्रमों का शुभारंभ
- प्रदर्शनियां, मेले और सामुदायिक सहभागिता गतिविधियां
- कौशल विकास, रोजगार और किसान केंद्रित गतिविधियां
- महिला सशक्तीकरण और समावेशन पहल
- मीडिया प्रचार और सोशल मीडिया अभियान
- सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी
- महिला और युवा केंद्रित सशक्तीकरण पहल
- सहकारी समितियों में नई आईटी तकनीक का उपयोग
- एक पेड़ मां के नाम अभियान
- स्वच्छता में सहकार पहल
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, नोडल विभागों और सहकारी संस्थानों के सक्रिय सहयोग ने इस राष्ट्रव्यापी उत्सव को सुगम बनाया।

इन प्रयासों से तय होगा सहकारिता का भविष्य

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सहकारिता के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विकास को बढ़ावा देना, विश्व स्तर पर सहायक कानूनी और नीतिगत ढांचों की वकालत करना और युवाओं को सहकारी आंदोलन को बनाए रखने और विस्तारित

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान सहकारिता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और सहकारी संगठनों द्वारा लोगो और डाक टिकट का उपयोग किया।

सदस्यों की सहभागिता बढ़ाने और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाएंगे।

सतत और समावेशी विकास

सहकारिता क्षेत्र का विस्तार होने से सहकारी समितियां सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी प्रथाओं को अपनाएंगी, जिनमें जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, पारिस्थितिक स्थिरता और सामाजिक समानता शामिल हैं। समावेशी मॉडल व्यापक आर्थिक भागीदारी को सुगम बनाएंगे, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों तक लाभ पहुंचेगा और सामाजिक न्याय एवं सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा। सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सहकारी समितियों के बीच साझेदारियां सहकारी आंदोलन के प्रभाव को मजबूत करेंगी। यह गठबंधन सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक जीवंत सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करेंगे।

ये प्राथमिकताएं सहकारिता मंत्रालय के उस एजेंडे के अनुरूप हैं जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को समावेशी और सतत विकास की आधारशिला बनाना है। यह प्रतिबद्धता 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जिसमें सहकारी समितियों को ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्थाओं, साझा समृद्धि और सतत राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाना तय किया गया है।

> **भारत में सहकारिता आंदोलन परिवर्तन के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसा युग जो नवाचार, समावेशिता और राष्ट्र की समृद्धि को गति देने के सामूहिक संकल्प द्वारा परिभाषित है। भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इसे नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गया था।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

करने के लिए प्रेरित करने वाले नेतृत्व को प्रोत्साहित करना था। सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए भविष्य की कार्ययोजना संस्थागत क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। इसमें शासन, पारदर्शिता और समावेशिता में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। सहकारी समितियों के भीतर नेतृत्व की भूमिकाओं और नवाचार के लिए महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन प्रयासों को लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शिक्षा और ज्ञान साझाकरण के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा ताकि समकालीन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम लचीले सहकारी उद्यम तैयार किए जा सकें।

सहकारी समितियों के प्रभावी संचालन के लिए नीतिगत और कानूनी सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे जो सहकारी समितियों को समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रेरक के रूप में मान्यता दें। साथ ही फाइनेंस, मार्केट और टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच को सुगम बनाएं। ऐसे सुधार यह सुनिश्चित करेंगे कि सहकारी समितियां सहयोगी माहौल में काम करें जो विकास, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को बढ़ावा दे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आधुनिक टेक्नोलॉजी का एकीकरण सहकारी समितियों की परिचालन क्षमता, पहुंच और सेवा वितरण को बढ़ाएगा। डिजिटल टूल्स सहकारी समितियों को प्रासंगिक बने रहने,

महिला एवं युवा सशक्तीकरण पर फोकस

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान महिलाओं और युवाओं को सहकारिता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में युवा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में सहकारिता के सिद्धांतों और इतिहास के

साथ-साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं और पहलों की विस्तृत जानकारी दी गई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सहकारिता की समझ को बढ़ाना और युवाओं को सहकारी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, विभिन्न राज्यों के सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों, संगठन और फेडरेशन के अलावा राज्य स्तरीय सहकारी संघों ने भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर विकसित भारत में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। समर्थ युवा, समर्थ सहकार की भावना से प्रेरित देशभर में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सहकारी उद्यमिता, स्वरोजगार, डेयरी, ऋण समितियों और स्टार्टअप में आर्थिक विकास जैसे विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के सहयोग से सामूहिक उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रख कर आयोजित किए गए ऐसे कार्यक्रमों में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, सहकारी साक्षरता शिविर और सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका फोकस युवा और महिला सहकारी सदस्यों के बीच नेतृत्व, आर्थिक भागीदारी और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने पर था। यही नहीं, कई राज्यों में नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जिसका उद्देश्य युवा और महिला नेताओं की अगली पीढ़ी को पोषित करना था, उन्हें सहकारी शासन को मजबूत करने और इस क्षेत्र में समावेशी, सतत विकास को गति देने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और दूरदृष्टि प्रदान करना था। राज्य स्तरीय युवा सहकार संवाद

जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसके माध्यम से विकास में सहकारिता की भूमिका पर छात्रों और युवाओं से बातचीत की गई और उनमें सहकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल की गई।

सहकारी निर्णय लेने में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र में नई ऊर्जा, नवाचार और स्थिरता लाने पर भी इस वर्ष के दौरान ध्यान केंद्रित किया गया। इससे कौशल आधारित रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिला। युवाओं पर केंद्रित मैराथन और सेमिनारों में भी छात्रों और युवा सहकारी सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इन गतिविधियों ने सहकारी आंदोलन में युवाओं की सहभागिता, जागरूकता और नेतृत्व को प्रोत्साहित करके अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के सूत्र वाक्य 'सहकार के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना' को मजबूत किया।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 ने देश में न सिर्फ सामाजिक समानता को मजबूत किया और भागीदारी को व्यापक बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सहकारी समितियां समावेशी और भविष्योन्मुखी बनी रहें, बल्कि जीडीपी में सहकारिता का योगदान बढ़ाने के प्रयासों को नई राह दिखाई है। सहकारिता बेहतर भविष्य का निर्माण करती हैं, इस थीम को इस वर्ष ने पूरी तरह से सफल बनाया। ■

महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रख कर आयोजित किए गए ऐसे कार्यक्रमों में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, सहकारी साक्षरता शिविर और सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका फोकस युवा और महिला सहकारी सदस्यों के बीच नेतृत्व, आर्थिक भागीदारी और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने पर था।

कृषि, पशुपालन और सहकारिता के संगम से ग्रामीण हो रहे समृद्ध

सहकारिता से जुड़कर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है कृषि व पशुपालन क्षेत्र, 11 वर्षों में केंद्र ने कृषि बजट छह गुना और ग्रामीण विकास बजट दोगुना किया

हरियाणा में मिल्क चिलिंग सेंटर, हेफेड आटा मिल, रुपे प्लेटिनम कार्ड, मॉडल पैक्स का पंजीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के पोर्टल का अमित शाह ने किया लोकार्पण

युवा सहकार टीम

गांवों में रहने वाली देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जीवन-यापन के लिए खेती-किसानी और पशुपालन पर निर्भर है। देश में सबसे अधिक रोजगार जिन दो क्षेत्रों में सृजित होता है, वह कृषि और पशुपालन ही है। कृषि और पशुपालन को सहकारिता से जोड़कर यह क्षेत्र करोड़ों लोगों को न केवल रोजगार उपलब्ध कराता है, बल्कि उन्हें समृद्ध बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों हरियाणा के पंचकूला में कृभको द्वारा 'सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका' विषय पर आयोजित सहकारी सम्मेलन में कहा कि हमने हमेशा कृषि और पशुपालन को केवल रोजगार की दृष्टि से देखा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर देश को 'सहकार से समृद्धि' का एक नया मंत्र दिया। इसके माध्यम से अब ग्रामीणों के रोजगार के साथ-साथ उनकी समृद्धि का काम भी हो रहा है। अमूल की शानदार उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में अमूल आज 36 लाख महिला दुग्ध उत्पादकों को हर साल लगभग 90 हजार करोड़ रुपये वितरित करती है। यह इसलिए संभव होता है क्योंकि अमूल दुग्ध उत्पादकों से प्राप्त दूध को विभिन्न उत्पादों में प्रसंस्कृत करके बाजार में उन्हें बेचता है जिससे उसे अधिक आय होती है। लेकिन यदि इतने ही दूध को बाजार मूल्य पर बेचा जाए, तो वह मात्र 12 हजार करोड़ रुपये में बिकता। यह अंतर सहकारिता की ताकत से पैदा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि पशुपालन, कृषि और सहकारिता, इन तीनों को जोड़कर 'सहकार से समृद्धि' का सृजन किया जा सकता है।

अमूल की स्थापना के समय रोजाना मात्र 2,000 लीटर दूध इकट्ठा होता था। आज यह देशभर में लगभग 3 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन इकट्ठा करता है और इसका टर्नओवर लगभग

एक लाख 23 हजार करोड़ रुपये है। उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा कि आने वाले 15 वर्षों में देश में अमूल जैसी किसानों के लिए काम करने वाली कम से कम 20 मजबूत सहकारी संस्थाएं खड़ी होंगी। कृषि और सहकारिता के सहयोग से हरियाणा भी आज किसानों की समृद्धि के नए आयाम लिख रहा है। इस राज्य ने देश की खाद्य सुरक्षा, दूध उत्पादन और खेलों के मैदान में हमेशा देश के लिए पदकों की झड़ी लगाने का काम किया है। उस कालखंड को भारत भूल नहीं सकता, जब आबादी कम होने के बावजूद खाने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ता था। यह हरियाणा और पंजाब की ही भूमि है जिसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया में सम्मान दिलाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 24 फसलें खरीदने वाला पहला राज्य हरियाणा ही है। यहां 48 घंटे के भीतर किसानों से हुई खरीदी का भुगतान कर दिया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर आयोजित कृभको के इस सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने मिल्क चिलिंग सेंटर, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन (हेफेड) का आटा मिल, रुपे प्लेटिनम कार्ड, मॉडल पैक्स का पंजीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में देशभर में हुए कार्यक्रमों, सेमिनार, प्रदर्शनी और अन्य गतिविधियों पर आधारित एक पोर्टल का लोकार्पण किया। इससे पूरे देश की सहकारिता से जुड़ी सूचनाएं सहकारिता से जुड़े सभी किसानों तक पहुंचेगी। हरियाणा सरकार के गन्ना किसानों को सबसे अधिक मूल्य देने की उपलब्धि पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार ने हरियाणा के किसानों को खुशहाल बना दिया है।

किसानों को मिलेगा कृषि व पशुपालन का पूरा मुनाफा

शाह के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना इसीलिए की गई, ताकि कृषि और पशुपालन के माध्यम से होने वाली उपज एवं उत्पादन का पूरा मुनाफा किसानों तक पहुंच सके। मंत्रालय की स्थापना के बाद प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए मॉडल बायलॉज तैयार किए गए हैं और मल्टीपर्पज पैक्स के प्रमाण-पत्र किसानों को दिए हैं। उर्वरक वितरण, कीटनाशक वितरण, कृषि उत्पादों की सफाई, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, दवाइयों की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, पानी का वितरण आदि सभी सेवाओं को पैक्स के साथ जोड़ा गया है। इस तरह लगभग 30 अलग-अलग आयामों को पैक्स के साथ जोड़कर सरकार ने पैक्स को मजबूत किया है। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर तीन मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी बनाई गई है। इनमें किसानों की उपज का निर्यात करने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल), ऑर्गेनिक उत्पादों की मार्केटिंग और प्रमाणीकरण के लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और बीज के उत्पादन, खरीद और वितरण के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) शामिल हैं। इन पहलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की मजबूत नींव डाली गई है। ■

कृषि बजट छह गुना बढ़ा

अमित शाह ने कहा कि 2014 में जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब देश का कृषि बजट 22 हजार करोड़ रुपये था। सरकार ने इसे बढ़ाकर एक लाख 27 हजार करोड़ रुपये किया है। ग्रामीण विकास का बजट 80 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर एक लाख 87 हजार करोड़ रुपये हो चुका है। आज कोई ग्राम पंचायत ऐसा नहीं है और हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं, जिसे पिछले 10 साल में 10 करोड़, 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपये गांव के विकास के लिए न मिला हो। विकास के दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि सरकार ने ढेर सारी पहलों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत किया है।

अन्न भंडारण योजना के लिए मिली छूट

सहकारी क्षेत्र के माध्यम से चलाई जा रही विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना

7 करोड़ टन भंडारण क्षमता होगी विकसित, इच्छुक सहकारी समितियां भी अब बना सकेंगी गोदाम

युवा सहकार टीम

देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत करने और अन्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के स्तर पर 7 करोड़ टन भंडारण क्षमता विकसित की जानी है। यह योजना 31 मई, 2023 को शुरू की गई थी। योजना की प्रगति को लेकर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा के बाद सरकार ने अब इसमें कुछ छूट देने की घोषणा की है। पहले इस योजना का क्रियान्वयन सिर्फ पैक्स द्वारा किया जाना था, लेकिन अब कार्यान्वयन क्षमता को व्यापक बनाने और परियोजना के विस्तार के उद्देश्य से इच्छुक सभी सहकारी समितियों, सहकारी संघों तथा बहु-राज्य सहकारी समितियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा भी पैक्स को सब्सिडी, मार्जिन मनी सहित कई तरह की छूट दी गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है।

अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण के अलावा विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं जैसे- कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि का निर्माण शामिल है। इसका उद्देश्य पैक्स की परिचालन क्षमता और आय को बढ़ाना और उन्हें बहु-सेवा केंद्रों में बदलना है, ताकि वह अन्य सुविधाओं के साथ स्थानीय स्तर पर भंडारण, प्रसंस्करण, वित्तीय और ऋण सेवाओं की सुविधा प्रदान कर सकें। इन सेवाओं से गोदामों के निर्माण चरण के दौरान रोजगार सृजित करके और योजना से संबंधित परिचालन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और अन्य सेवाओं के लिए दीर्घकालिक रोजगार सृजन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए उनके उपज की बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना, परिवहन लागत को कम करना और समग्र रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना भी है।

इनमें मिली छूट

यह योजना केंद्र सरकार की विभिन्न मौजूदा स्कीमों जैसे- कृषि अवसंरचना निधि, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पैक्स की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए इन योजनाओं में उपयुक्त संशोधन करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए

हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कृषि अवसंरचना निधि के तहत पैक्स के लिए ऋण चुकाने की अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। साथ ही, कृषि विपणन अवसंरचना योजना के तहत पैक्स के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पैक्स अब गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि के निर्माण के लिए योजना की लागत का 90 प्रतिशत तक कर्ज ले सकेंगे। इसी तरह, निर्माण लागत को मैदानी क्षेत्र के लिए 3,000-3,500 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति टन और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 4,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। पैक्स के लिए सब्सिडी को भी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33.33 प्रतिशत कर दिया गया। मैदानी क्षेत्र के लिए पहले यह सब्सिडी 875 रुपये प्रति टन थी जिसे अब 2,333 रुपये प्रति टन और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,333 रुपये से 2,666 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। पैक्स के लिए आंतरिक सड़कों, धर्मकांटा, चारदीवारी आदि जैसी सहायक अवसंरचना के लिए कुल स्वीकृत सब्सिडी का एक तिहाई अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने का भी अब प्रावधान किया गया है।

गोदाम बनाने में राजस्थान अव्वल

इस योजना से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, खाद्यान्न की बर्बादी में कमी आएगी, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सकेगी। इस योजना के तहत देशभर में 112 पैक्स में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है जिनकी कुल भंडारण क्षमता 68,702 टन है। सबसे ज्यादा राजस्थान में 82 पैक्स ने इस योजना के तहत अब तक गोदामों का निर्माण किया है। पैक्स की इस बढ़ती हुई भूमिका का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, फसल कटाई पश्चात अनाजों के नुकसान को कम करना, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करना और कृषि-संचालित विकास में सकारात्मक योगदान देना है।

महत्वपूर्ण बदलाव

- **सभी सहकारी समितियां, सहकारी संघ और बहु-राज्य सहकारी समितियां योजना में शामिल**
- **एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत पैक्स के लिए कर्ज चुकाने की अवधि बढ़कर 10 वर्ष हुई**
- **एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत मार्जिन मनी को घटाकर 10 प्रतिशत किया गया**
- **प्रति टन विनिर्माण लागत को मैदानी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बढ़ाकर किया गया दोगुना**
- **पैक्स के लिए सब्सिडी को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33.33 प्रतिशत किया गया, सहायक अवसंरचनाओं के लिए कुल सब्सिडी की एक तिहाई अतिरिक्त सब्सिडी का भी हुआ प्रावधान**

पैक्स को अतिरिक्त आय

इस योजना के तहत निर्मित गोदामों को एफसीआई, सीडब्ल्यूसी (केंद्रीय भंडारगारण निगम) और राज्यों के भंडारगारण निगमों द्वारा किराये पर ले लिया जाता है जिससे पैक्स को अतिरिक्त आमदनी होती है। 2,500 टन और उससे अधिक क्षमता के सभी गोदामों को 9 साल के लिए एक समान किराये पर लेने को एफसीआई राजी हो गया है। इस योजना के तहत पैक्स को चिह्नित करने, गोदामों का निर्माण, किराया आश्वासन प्रदान करने, परिचालन सहायता प्रदान करने और निर्मित गोदामों के परिचालन उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई, नेफेड, एनसीसीएफ, राज्य भंडारगारण निगम और स्टेट मार्केटिंग फेडरशन जैसे संस्थानों को शामिल किया गया है। ■

इस योजना के तहत देशभर में 112 पैक्स में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है जिनकी कुल भंडारण क्षमता 68,702 टन है। सबसे ज्यादा राजस्थान में 82 पैक्स ने इस योजना के तहत अब तक गोदामों का निर्माण किया है।

कैंपस कोऑपरेटिव से युव

युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय लगातार प्रयासरत है। नई सहकारिता नीति में भी इसके लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस कड़ी में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कैंपस कोऑपरेटिव बनाने के प्रावधान भी शामिल हैं। गुजरात के अमरेली जिला सहकारी संघ के युवा अध्यक्ष **मनीष संघाणी** राज्य के विभिन्न कॉलेजों में कैंपस कोऑपरेटिव बनाने को लेकर काफी सक्रिय हैं। इस बारे में **अभिषेक राजा** और **नुरुल कौसैन** ने उनसे विस्तार से बातचीत की और यह समझने की कोशिश की कि युवाओं को कोऑपरेटिव के प्रति आकर्षित करने में यह कैसे सहायक है। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

कैंपस कोऑपरेटिव क्या है और यह कैसे काम करता है?

वर्ष 2021 में जब पहली बार केंद्रीय स्तर पर अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह ने युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए कैंपस कोऑपरेटिव बनाने का सुझाव दिया था। उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए ही मैंने अमरेली शहर में स्थित कमानी साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज में और सावरकुंडला तहसील स्थित आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में कोऑपरेटिव सोसायटी बनाई। उनके बायलॉज इस तरह के बनाए गए हैं कि उनमें कोई प्रोफेसर या कर्मचारी चेयरमैन या डायरेक्टर नहीं हो सकते। फाइनल ईयर का कोई छात्र ही चेयरमैन होगा और उसके पासआउट होते ही उसका कार्यकाल खुद ही समाप्त हो जाएगा। जबकि फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के छात्र सोसायटी के मेंबर और डायरेक्टर बन सकते हैं। युवाओं को कॉलेज स्तर से ही कोऑपरेटिव से जोड़ना होगा ताकि आगे चलकर जब वह इस क्षेत्र में काम करेंगे तो कॉलेज में मिला अनुभव उनके काम आएगा।

बुक से लेकर नोटबुक, पेन-पेंसिल एवं पढ़ाई की अन्य सामग्री सभी स्टूडेंट्स की जरूरत है। वह इसे कहीं न कहीं से जरूर खरीदते हैं। कैंपस कोऑपरेटिव के माध्यम से इन जरूरी सामानों को कॉलेजों या यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही उपलब्ध कराया जाता है। कोऑपरेटिव इन्हें थोक भाव में खरीदते हैं और सामान्य दुकानदारों की तुलना में कम मार्जिन पर बेचते हैं। स्टूडेंट्स को इससे दोहरा फायदा होता है। एक तो बाजार की तुलना में उचित कीमत पर उनकी जरूरत का सामान मिल जाता है, दूसरा, जो स्टूडेंट इसके सदस्य होते हैं उन्हें बिक्री से हुए मुनाफे में हिस्सेदारी भी मिलती है। मैंने उन्हें त्योहारों के दौरान कपड़े एवं अन्य सामानों को भी बेचने की सलाह दी है। पिछले साल इन कॉलेजों की छात्राओं ने रक्षाबंधन के दौरान राखी बनाकर कैंपस कोऑपरेटिव के माध्यम से बेची। इससे उन्हें मेहनताना तो मिला ही, कैंपस कोऑपरेटिव को जो आमदनी हुई उसमें भी हिस्सेदारी मिली। कैंपस कोऑपरेटिव को भी आमदनी बढ़ाने का नया माध्यम मिल गया। हमने बायलॉज में यह भी प्रावधान किया है कि जब कोऑपरेटिव की आमदनी बढ़ेगी और उनके पास पर्याप्त फंड हो जाएगा तो आर्थिक रूप से कमजोर टैलेंटेड स्टूडेंट्स की फीस भरने का फैसला भी बोर्ड ले सकेगा।

ाओं में बढ़ेगी जागरूकता

कैंपस कोऑपरेटिव को लेकर स्टूडेंट्स की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वे इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं?

कॉलेज स्टूडेंट्स में इसके बारे में जानकारी का अभाव है। हम उन्हें लगातार जागरूक कर रहे हैं। पहले वर्ष तो बहुत कम स्टूडेंट्स इसके सदस्य बने लेकिन जैसे-जैसे उनमें जागरूकता बढ़ रही है और उन्हें पता चल रहा है कि इससे जुड़ने का क्या फायदा है, वैसे-वैसे स्टूडेंट्स इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। जिन कॉलेजों में हमने कैंपस कोऑपरेटिव बनाया है वहां के प्रिंसिपल को भी पहले इसकी जानकारी नहीं थी। हमने उन्हें जब इसके फायदे के बारे में विस्तार से समझाया तो वह कैंपस कोऑपरेटिव बनाने में सहयोग देने को राजी हो गए। गुजरात में कोऑपरेटिव सोसायटी बनाने के लिए न्यूनतम 100 सदस्यों और 1,000 रुपये के शेयर की आवश्यकता होती है। इसी तरह कोऑपरेटिव सोसायटी का बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए न्यूनतम 1 लाख रुपया जमा करना होता है। चूंकि इतने स्टूडेंट्स को एक साथ जोड़ना और उन्हें इतने रुपये देने के लिए राजी करना आसान नहीं था, इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनसे इस नियम में छूट देने का आग्रह किया। उन्होंने कैंपस कोऑपरेटिव के लिए सदस्यों की संख्या घटाकर 50 और शेयर लेने के लिए न्यूनतम 100 रुपये निर्धारित कर दिया। अब बारी बैंक खाता खुलवाने में छूट प्राप्त करने की थी। मैंने स्थानीय कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन से इस बारे में बात की। चूंकि मैं भी उस बैंक के बोर्ड में डायरेक्टर हूं तो बोर्ड में इस नए इनिशिएटिव को लेकर छूट देने का प्रस्ताव रखा जिसे बोर्ड ने स्वीकार करते हुए खाता खुलवाने की राशि घटाकर 5,000 रुपये कर दी। इससे छात्रों को जोड़ने में बड़ी राहत मिली। अमरेली जिले में मौजूद सभी कॉलेजों में कैंपस कोऑपरेटिव बनाना मेरा मकसद है और हम इस योजना पर लगातार काम कर रहे हैं।

युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए सरकार के प्रयासों के अलावा और क्या किया जाना चाहिए?

सरकार जो प्रयास कर रही है वह तो ठीक है, लेकिन युवाओं को भी इसके लिए आगे आना होगा। जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उनके लिए कोऑपरेटिव नहीं है। जो अपने आसपास के लोगों, समाज, समुदाय एवं देश की भलाई के बारे में सोचते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं वही कोऑपरेटिव में अच्छा काम कर सकते हैं। देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं दिखाई जा सकती, बल्कि अच्छी कोऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से भी लोगों, समाज एवं देश की सेवा की जा सकती है। लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने से सरकार पर कम बोझ पड़ेगा और सरकार को उनके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। 'मैं नहीं, सबकी' सोच के साथ युवा आगे बढ़ेंगे तो देश खुद आगे बढ़ेगा।

कोऑपरेटिव सोसायटीज में युवा नेतृत्व बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

युवाओं को इसके लिए खुद रुचि जगानी होगी। कोऑपरेटिव सेक्टर में राजनीति है लेकिन वह अलग तरह की है। आप खुद ही सोसायटी बनाकर कोऑपरेटिव सेक्टर में अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं और नेतृत्व क्षमता हासिल कर सकते हैं। सोसायटी बनाने की कोई सीमा तो है नहीं। अपनी क्षमता के हिसाब से सोसायटी बनाकर काम कर सकते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। ■

सहकारिता सुधारों पर राष्ट्रीय विमर्श

सहकार से समृद्धि के विजन के तहत उदयपुर में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में हुई समीक्षा

पैक्स, सहकारी बैंकिंग और डिजिटल पहलों को सुदृढ़ करने पर राज्यों और केंद्र में हुआ विचार-विमर्श

पैक्स सशक्तीकरण, अनाज भंडारण और सहकारी नवाचार पर राज्यों ने साझा की सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धतियां

युवा सहकार टीम

सहकारिता क्षेत्र को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ राजस्थान के उदयपुर में 8-9 जनवरी, 2026 को राष्ट्रीय स्तर की दो दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया एवं सहकारिता को विकास का मजबूत स्तंभ बनाने पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के सचिव स्तरीय प्रतिभागियों ने मॉडल बायलॉज, बैंकिंग क्षेत्र में आरबीआई की भूमिका, सहकारी बैंकों, मल्टी-पर्पज पैक्स तथा डेयरी क्षेत्र में किए गए प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और उनकी आर्थिक भागीदारी का विस्तार करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय व्यापक सुधारों को अमल में ला रहा है।

इस कार्यशाला और समीक्षा बैठक का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने किया। उद्घाटन भाषण में डॉ. भूटानी ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय को और मजबूत करना, विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना तथा सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए नवाचारी दृष्टिकोण अपनाना है। सहकारी संस्थाएं वर्षों तक हाशिये पर रहीं। इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए जन-धारणा को फिर से आकार देने तथा पारंपरिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक सफलता की कहानियों को उजागर करने की आवश्यकता है। बनासकांठा डेयरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक सूखा प्रभावित जिले ने सशक्त और एकीकृत वैल्यू चेन के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 90 लाख लीटर दूध उत्पादन हासिल किया। यह सहकारी संस्थाओं की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने सहकारी बैंकों के द्वि-नियमन से जुड़े मुद्दों के समाधान, बोर्ड चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार, जमीनी हकीकत को समझने के लिए फील्ड विजिट तथा सहमति आधारित निर्णय संस्कृति को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख सुधारों पर बल दिया। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी सहकारी बैंकों के लिए नियमों को सरल बनाने और प्रशासनिक कमियों को दूर करने के लिए आरबीआई एवं वित्त मंत्रालय के साथ सहकारिता मंत्रालय के सतत संवाद को भी रेखांकित किया।

डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डाला। इनमें स्वयं सहायता समूहों का सहकारी संस्थाओं के साथ एकीकरण, कम लागत वाले चालू और बचत खाता (उअरअ) फंड बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थानों को केवल सहकारी बैंकों में खाता खोलने का प्रावधान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष समर्थन तथा त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी और मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण शामिल हैं। उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और वैल्यू-चेन विकास जैसी पहलों के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र के आर्थिक योगदान को तीन गुना करने के विजन को दोहराया।

दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान एक समीक्षा सत्र का आयोजन किया गया जिसमें सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई। इनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों तथा सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण, मॉडल पैक्स, बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समिति और बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समिति जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। इस दौरान हुई चर्चाओं में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना तथा पैक्स द्वारा प्रदान की जा रही अतिरिक्त सेवाओं- जैसे कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के विस्तार पर भी विचार-विमर्श हुआ। सहकारी बैंकिंग सुधारों और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड तथा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जैसी पहलों के साथ-साथ श्वेत क्रांति 2.0 के संवर्धन पर भी चर्चा की गई।

कार्यशाला का एक अन्य प्रमुख फोकस राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस को सुदृढ़ करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों में सुधारों को आगे बढ़ाने पर रहा। कार्यशाला के दूसरे दिन 'सहकार से समृद्धि-पैक्स आगे' शीर्षक से एक समर्पित सत्र आयोजित किया गया जिसमें लक्ष्य आधारित पहलों के माध्यम से पैक्स को सशक्त बनाने पर फोकस किया गया। पैक्स के पुनरुद्धार में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया, जिसमें राज्यों ने अपने अनुभव और सर्वोत्तम कार्यपद्धतियां साझा की। इस सत्र में पैक्स को सुदृढ़ करने, उनकी वित्तीय स्थिरता बढ़ाने तथा उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने हेतु एक समग्र रणनीति को रेखांकित किया गया। विशेष सत्रों में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सहकारिता विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। 'सहकार संवादः सफल सहकारिताओं के साथ संवाद' सत्र में प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य और डेयरी पहलों पर अनुभव साझा किए गए।

अपने समापन संबोधन में सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने अनाज भंडारण योजना को गति देने के लिए किराया गारंटी प्रदान की है। इसके तहत सितंबर 2026 तक 5 लाख टन और सितंबर 2027 तक 50 लाख टन भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह लक्ष्य कैसे पूरा किया जाएगा और एक साल में ही 10 गुना क्षमता कैसे विकसित कर ली जाएगी। मई 2023 में इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक सिर्फ 68,702 टन क्षमता के गोदाम ही बनाए जा सके हैं, जबकि योजना के तहत 7 करोड़ टन भंडारण क्षमता निर्माण करने का लक्ष्य तय किया गया है।■

इस दौरान हुई चर्चाओं में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना तथा पैक्स द्वारा प्रदान की जा रही अतिरिक्त सेवाओं- जैसे कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के विस्तार पर भी विचार-विमर्श हुआ। सहकारी बैंकिंग सुधारों और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड तथा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जैसी पहलों के साथ-साथ श्वेत क्रांति 2.0 के संवर्धन पर भी चर्चा की गई।

AI से एक साल में लैस होंगे 10 लाख युवा

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान से मेगा स्किलिंग अभियान की शुरुआत की

जयपुर में बनेगा आधुनिक डेटा सेंटर जिससे देश की डिजिटल क्षमता को मिलेगी नई मजबूती

नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026, आईस्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पोर्टल तथा राजस्थान एआई पोर्टल का हुआ शुभारंभ

युवा सहकार टीम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अब पूरी दुनिया में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और भविष्य की जरूरत बन चुका है। इसकी जरूरत हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में शासन, उद्योग और आम जीवन की दिशा एआई तय करेगा। भारत अभी एआई कौशल में अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले पीछे है। हालांकि, भारतीय युवाओं में एआई कौशल से लैस होने की पर्याप्त क्षमता है जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राजस्थान से एक मेगा स्किलिंग अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का लक्ष्य एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को एआई कौशल प्रदान करना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में इसकी घोषणा की। यह अभियान न केवल युवाओं को रोजगार योग्य बनाएगा, बल्कि छोटे व्यवसायों में उत्पादकता बढ़ाने और दैनिक जीवन में एआई के उपयोग को बढ़ावा देगा। केंद्रीय आईटी मंत्री ने एआई का एक डेटा सेंटर जयपुर में बनाने की भी घोषणा की। यह देश का बड़ा डेटा सेंटर होगा जिससे डिजिटल क्षमता को नई मजबूती मिलेगी। जल्द ही इसका भूमि पूजन होगा।

जयपुर में आयोजित तीन दिवसीय राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 के अंतिम दिन राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तेजी से हो रहे 5जी रोलआउट की तरह ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रतिभा विकास और एआई कौशल विकास का काम भी उतनी ही तेजी से होगा। एआई रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गई है। ठीक उसी तरह जैसे कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, इंटरनेट और मोबाइल फोन द्वारा संचालित पिछली तकनीकी क्रांतियां थीं। उन्होंने इसके भविष्य की तुलना बिजली से की जिसने एक समय

में हर घर और व्यक्ति तक पहुंच कर समाज को नया रूप दिया था। भारत में एआई के प्रति दृष्टिकोण के बारे में आईटी मंत्री ने कहा कि इस दृष्टिकोण का पहला मार्गदर्शक सिद्धांत एआई का लोकतंत्रीकरण है और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक को प्रौद्योगिकी तक पहुंच और इसके उपयोग का समान अवसर प्राप्त हो। भारत के एआई मिशन को वैश्विक मान्यता मिल चुकी है और कई देश एआई के लोकतंत्रीकरण के भारत के मॉडल का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। इस मिशन का एक प्रमुख स्तंभ किफायती कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में उच्च गुणवत्ता वाली कंप्यूटिंग सुविधाओं को बहुत कम लागत पर उपलब्ध कराने का विचार पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र, स्टार्टअप, युवा, वैज्ञानिक और इंजीनियर वित्तीय बाधाओं के बिना विश्व स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग कर सकें।

एआई विकास के क्षेत्र में भारत आज विश्व के शीर्ष तीन देशों में शामिल है। चीन, अमेरिका और भारत एआई विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भारत जल्द ही एक वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की आईटी इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी ताकत है। एआई के माध्यम से यह शक्ति और सुदृढ़ होगी।

इंडिया एआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह ने इस अवसर पर कहा कि एआई के इस्तेमाल से कुछ नौकरियां कम हो सकती हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में उसके मुकाबले कई गुणा अवसर बढ़ेंगे। जब भी टेक्नोलॉजी का कोई नया क्षेत्र आता है तो नई नौकरियां सृजित भी होती हैं। एआई के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार किए जा सकते हैं। अभिषेक सिंह के अनुसार, भारत को वैश्विक एआई सेवाओं का उपभोक्ता बने रहने की बजाय आत्मनिर्भर एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी एआई वैल्यू चेन में क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एआई इस सदी में मानवता के लिए एक नया कोड गढ़ रहा है। उन्होंने इसे राजस्थान की विकास यात्रा का अहम इंजन बताते हुए कहा कि सरकार इसके विवेकपूर्ण उपयोग से ई-गवर्नेंस को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बना रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026, आईस्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पोर्टल तथा राजस्थान एआई पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इन पहलों के माध्यम से राज्य में एआई आधारित शिक्षा, स्टार्टअप्स, शोध, कौशल विकास और डिजिटल गवर्नेंस को नई गति मिलेगी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान को आईटी हब बनाने में एआई-एमएल नीति 2026 और राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में एआई की शिक्षा अनिवार्य होगी और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने गूगल और आईआईटी दिल्ली जैसी संस्थाओं के साथ समझौते किए हैं। गूगल के सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और नागरिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में एआई-एमएल आधारित पायलट परियोजनाओं के माध्यम से शासन को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही क्लाउड और एआई कार्यान्वयन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ मिलेगा। आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी से एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, शोध, स्किलिंग, हैकाथॉन, स्टार्टअप मेंटरिंग और उद्योग-शैक्षणिक-सरकारी सहयोग को मजबूती मिलेगी। जबकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के सहयोग से राज्य में विश्वसनीय, उत्तरदायी और नैतिक एआई को बढ़ावा देते हुए सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स और पेशेवरों का क्षमता निर्माण किया जाएगा।■

एआई विकास के क्षेत्र में भारत आज विश्व के शीर्ष तीन देशों में शामिल है। चीन, अमेरिका और भारत एआई विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भारत जल्द ही एक वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की आईटी इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी ताकत है। एआई के माध्यम से यह शक्ति और सुदृढ़ होगी।

पुस्तकों, विचारों और संस्कृति का जन-उत्सव

युवा सहकार टीम

> इस महोत्सव की सफलता इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल युग में भी पुस्तकों का आकर्षण कम नहीं हुआ है, बल्कि नई पीढ़ी के बीच यह और अधिक सशक्त हुआ है। इस दौरान तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने।

वर्ष 2023 में आरंभ हुआ पुणे पुस्तक महोत्सव का तीसरा संस्करण 13-21 दिसंबर, 2025 को फर्ग्युसन कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया। तीन वर्षों में यह आयोजन न केवल आकार में बड़ा हुआ है, बल्कि इसने साहित्य प्रेमियों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई है। यह एक ऐसा साहित्यिक उत्सव बन गया है जो जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के साथ जीवंत होता है। इस महोत्सव की सफलता इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल युग में भी पुस्तकों का आकर्षण कम नहीं हुआ है, बल्कि नई पीढ़ी के बीच यह और अधिक सशक्त हुआ है। इस दौरान तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इसका प्रमाण-पत्र महोत्सव के आयोजकों को सौंपा।

पुणे पुस्तक महोत्सव 2025 ने फर्ग्युसन कॉलेज मैदान को ज्ञान, संवाद और सांस्कृतिक ऊर्जा के एक जीवंत केंद्र में परिवर्तित कर दिया। दिसंबर की गुलाबी ठंड में धूप से नहाया पुणे और वर्ष के अंत के उत्सवी माहौल से यह आयोजन केवल एक पुस्तक मेला नहीं, बल्कि पढ़ने की संस्कृति का सामूहिक उत्सव बनकर उभरा। इस वर्ष महोत्सव की थीम 'जॉय ऑफ रीडिंग' थी जो हर गतिविधि, हर मंच और हर पाठक के अनुभव में स्पष्ट रूप से दिखी।

इस महोत्सव की परिकल्पना और नेतृत्व मुख्य आयोजक राजेश पांडे द्वारा किया गया, जबकि इसका सह-आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपने निदेशक युवराज मलिक के मार्गदर्शन में समर्थ युवा फाउंडेशन, पुणे के सहयोग से किया। यह साझा प्रयास पुणे को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक मंच पर एक सशक्त पहचान दिलाने में सफल रहा। इस महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और महाराष्ट्र के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. सुरेश गोसावी और नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष मिलिंद माराठे की उपस्थिति ने आयोजन को अकादमिक और संस्थागत गरिमा प्रदान की।

पुणे लिटरेचर फेस्टिवल

पुणे पुस्तक महोत्सव के दौरान 16 से 21 दिसंबर तक पुणे लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया जो इस महोत्सव की वैचारिक आत्मा रही। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। इस मंच पर साहित्य, पत्रकारिता, पर्यावरण, सिनेमा, संगीत, अनुवाद और भारतीय ज्ञान परंपरा पर गहन संवाद हुआ। बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक, ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज, फिल्मकार सिद्धार्थ काक और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जैसे प्रतिष्ठित वक्ताओं ने इसमें सहभागिता की। युवाओं और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी ने इन चर्चाओं को विशेष रूप से जीवंत बनाया।

पुस्तकों की विविध दुनिया

महोत्सव परिसर में प्रवेश करते ही पाठकों को एक विस्तृत साहित्यिक संसार में कदम रखने का अनुभव हुआ। इस वर्ष लगभग 900 स्टॉल लगाए गए जिनमें से 800 से अधिक स्टॉल पूरी तरह पुस्तकों के लिए समर्पित थे। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी सहित अनेक भारतीय भाषाओं की पुस्तकों ने देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सजीव रूप दिया। इस महोत्सव में हर आयु और रुचि के पाठकों के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध था, जैसे- शैक्षणिक ग्रंथ, समकालीन साहित्य, बाल पुस्तकें, आत्मकथाएं और शोध ग्रंथ आदि।

महोत्सव की उपलब्धियां

इस महोत्सव की सफलता की कहानी आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं। 9 दिन तक चले पुस्तक महोत्सव में 12,50,000 से अधिक साहित्य प्रेमियों ने शिरकत की, जबकि लगभग 30 लाख पुस्तकों की बिक्री हुई। इस दौरान 50 करोड़ रुपये से अधिक का कुल कारोबार हुआ। 1,200 से अधिक लेखकों और वक्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया और 498 से अधिक पुस्तकों का विमोचन हुआ। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि जॉय ऑफ रीडिंग केवल एक थीम नहीं, बल्कि जनमानस से जुड़ा हुआ अनुभव बन चुका है।

वैश्विक पहचान

पुणे पुस्तक महोत्सव 2025 के दौरान तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जो सामाजिक चेतना, पर्यावरणीय जागरूकता और सामूहिक साहित्यिक सहभागिता के प्रतीक बने। इस पुस्तक महोत्सव में पोस्टरों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया जिसके लिए गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज किया गया। साथ ही, दुनिया के सबसे बड़े फोटो शब्द और शपथ लेते लोगों का सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो एल्बम का गिनीज रिकॉर्ड भी इस दौरान बना। 2023 से शुरू हुए पुणे पुस्तक महोत्सव ने अब तक 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। समापन समारोह में आयोजकों, स्वयंसेवकों, लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों ने इस साझा यात्रा को स्मरण करते हुए भविष्य के संस्करणों के लिए नई प्रतिबद्धताएं व्यक्त कीं। इस महोत्सव ने यह साबित किया कि पढ़ना आज भी एक जीवंत, सामाजिक और सामूहिक अनुभव है। यह महोत्सव अब केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि पुणे की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, जहां किताबें वर्तमान को समृद्ध करती हैं, भविष्य को आकार देती हैं और जॉय ऑफ रीडिंग को हर पाठक के हृदय में जीवित रखती है।■

इसने साबित किया कि पढ़ना आज भी एक जीवंत, सामाजिक और सामूहिक अनुभव है। यह महोत्सव अब केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि पुणे की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, जहां किताबें वर्तमान को समृद्ध करती हैं, भविष्य को आकार देती हैं और जॉय ऑफ रीडिंग को हर पाठक के हृदय में जीवित रखती है।

युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही एनवाईसीएस

असम के चौथे सहकारिता मेले में सतत विकास के लिए सहकारिता विषय पर एनवाईसीएस ने राज्य स्तरीय सम्मेलन का किया सफल आयोजन

सहकारिता युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें एनवाईसीएस की भूमिका है अत्यंत सराहनीय : जोगेन मोहन

युवा सहकार टीम

असम में सहकारिता आंदोलन की शक्ति, विविधता और संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए पिछले चार वर्ष से सालाना सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है। असम सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा 13-15 दिसंबर, 2025 तक गुवाहाटी में आयोजित चौथे सहकारिता मेले में समर्थ युवा फाउंडेशन और नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) द्वारा 'सतत विकास के लिए सहकारिता' विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक विकास, स्थिरता तथा कौशल विकास में सहकारिता की भूमिका पर गहन चर्चा करना एवं सहकारी आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाना था। यह सम्मेलन सहकारिता के माध्यम से सतत विकास, आर्थिक सशक्तीकरण और कौशल निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। इससे राज्य के सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा एवं दिशा प्राप्त हुई।

इस अवसर पर असम के सहकारिता, लोक निर्माण, पर्वतीय क्षेत्र तथा स्वदेशी एवं जनजातीय आस्था एवं संस्कृति मंत्री जोगेन मोहन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने राज्य में सहकारी मूल्यों के प्रसार और युवाओं के सशक्तीकरण के लिए एनवाईसीएस के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सहकारिता युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम है और इस दिशा में एनवाईसीएस की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। सम्मेलन के दौरान सात तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया जिनमें सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार और अनुभव साझा किए गए। इन सत्रों ने प्रतिभागियों को सहकारी संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप, भविष्य की संभावनाओं और व्यावहारिक चुनौतियों को समझने का अवसर प्रदान किया।

भारतीय किसान संघ (उत्तर-पूर्व) के संगठन सचिव कृष्ण कांत बोरा और सहकारी समितियों के ज्वाइंट रजिस्ट्रार (गुवाहाटी) बिस्वजीत चक्रवर्ती ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। दोनों वक्ताओं ने एनवाईसीएस द्वारा की जा रही पहलों की प्रशंसा करते हुए प्रतिभागियों एवं असम के विभिन्न जिलों से आए एनवाईसीएस जिला प्रतिनिधियों को बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। सम्मेलन के एक प्रमुख सत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहायक निदेशक

हितेश केवलरामानी ने भारत में सहकारिता की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने सहकारी आंदोलन के विकास, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को सरल शब्दों में समझाया। इस सत्र में यह स्पष्ट हुआ कि सहकारिता न केवल आर्थिक प्रगति का माध्यम है, बल्कि सामाजिक समावेशन और आत्मनिर्भरता का भी एक सशक्त उपकरण है।

असम राज्य सहकारी संघ के सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी श्यामल कुमार सैकिया ने सहकारी सदस्यों के लिए पंजीकरण-पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सहकारी संस्थाओं की मजबूती जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण से ही संभव है। इसके लिए प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक कदम है। गुवाहाटी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के निदेशक (प्रभारी) हेमंत कुमार दास ने सहकारी प्रबंधन शिक्षा के महत्व पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि सहकारी संस्थाओं के सफल संचालन के लिए पेशेवर प्रबंधन, पारदर्शिता और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। सम्मेलन में नुमालीगढ़ स्थित असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड (एबीईपीएल) के सहायक प्रबंधक (सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स) डॉ. प्रणब कुमार नाथ ने बांस ऊर्जा खेती, उभरती जैव-अर्थव्यवस्था और उसकी संभावनाओं पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि बांस आधारित ऊर्जा उत्पादन न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का भी एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।

स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के वरिष्ठ फील्ड अधिकारी उषम एस. सिंह ने उत्तर-पूर्व में मसाला क्षेत्र में निर्यात प्रोत्साहन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सहकारी सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए उपलब्ध अवसरों और सरकारी सहायता योजनाओं से अवगत कराया। जबकि केंद्रीय हस्तशिल्प विकास आयुक्त और क्षेत्रीय निदेशक हरकांत बरो ने सहकारी सदस्यों के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हस्तशिल्प सहकारिताएं स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाकर आजीविका के नए रास्ते खोल सकती हैं। इसके अतिरिक्त, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख अमित कुमार दास ने असम में कृषि कौशल विकास के महत्व को रेखांकित किया। ■

असम के युवाओं की प्रगति का माध्यम बन रही सहकारिता : गुर्जर

असम के चौथे सहकारिता मेले 2025 का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और असम के सहकारिता मंत्री जोगेन मोहन ने किया। इस अवसर पर कृष्णपाल गुर्जर ने असम के सहकारिता क्षेत्र में हो रहे तेज सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य स्तर पर सक्रिय और प्रभावी क्रियान्वयन के चलते असम प्रमुख राष्ट्रीय पहलों में अग्रणी बनकर उभरा है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के 100 प्रतिशत कंप्यूटरीकरण की दिशा में असम ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यहां 800 से अधिक पैक्स ने नए मॉडल बायलॉज को अपनाया है। इस प्रगति से युवाओं और महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है और राज्य के 32 लाख से अधिक सहकारी सदस्यों को वित्तीय समावेशन का लाभ मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम अब राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप पूरी तरह अग्रसर है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026 तक प्रत्येक गांव में एक सहकारी संस्था की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

सम्मेलन में सात तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया जिनमें सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार और अनुभव साझा किए गए।

एनवाईसीएस के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की सीएसआर पहल के सहयोग से हो रहा संचालित, समर्थ युवा फाउंडेशन भी है भागीदार

युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है उद्देश्य

युवा सहकार टीम

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की सीएसआर पहल के सहयोग से समर्थ युवा फाउंडेशन और नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) ने साथ मिलकर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले युवाओं को कौशल केंद्रित तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह पहल युवाओं में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने तथा एक कुशल एवं आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने की दिशा में एनवाईसीएस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 27 दिसंबर, 2025 को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

भारत की युवा आबादी में अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में देश के युवा बेरोजगारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी और स्थायी आजीविका के अवसरों के अभाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एनवाईसीएस और समर्थ युवा फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिसकी वित्तीय व्यवस्था इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा सीएसआर पहल के अंतर्गत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और रोजगार के बीच के अंतर को व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से दूर करना है। यह कार्यक्रम इस विश्वास पर आधारित है कि कौशल आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और दीर्घकालिक करियर विकास की मजबूत नींव होते हैं।

इस पहल के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण

प्रदान किया जा रहा है, जिनमें रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। कार्यक्रम के तहत युवाओं को असिस्टेंट ब्यूटी थैरेपिस्ट के रूप में पेशेवर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वह पर्सनल केयर और वेलनेस उद्योग में आत्मविश्वास के साथ अपने करियर की शुरुआत कर सकें। इसके साथ ही सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर के रूप में विकसित होने के लिए युवाओं की शिक्षण क्षमता और उद्यमशील सोच को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे वह स्वयं का रोजगार सृजित कर सकें। इसके अतिरिक्त, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन में तकनीकी प्रशिक्षण युवाओं को तेजी से बढ़ते सुरक्षा एवं निगरानी क्षेत्र में अवसर प्रदान करता है। जबकि पाइप फिटर (ऑयल एंड गैस/सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) का प्रशिक्षण शहरी बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं से जुड़े रोजगार के लिए उन्हें तैयार करता है। यह सभी प्रशिक्षण क्षेत्र युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दोनों के लिए सक्षम बनाते हैं।

इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में 120 पंजीकृत प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। युवाओं की सक्रिय सहभागिता और सीखने की उत्साह ने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाया। उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि युवा वर्ग अब कौशल विकास के महत्व को समझ रहा है और एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।

कार्यक्रम का उद्घाटन महिला उद्यमी एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनु सूद की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं को निरंतर सीखने और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया तथा कहा कि कौशल ही व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की कुंजी हैं। इस अवसर पर नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र साहू ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बताया कि किस प्रकार तकनीक का सकारात्मक और प्रभावी उपयोग किया जा

सकता है। इसके माध्यम से अपनी क्षमताओं और कौशल को और अधिक निखारा जा सकता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के कुणाल हजारी ने प्रतिभागियों को आईजीएल की विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी तथा उन्हें निरंतर प्रश्न करने और सीखते रहने के लिए प्रेरित किया। वीपी त्यागी, महिपाल दुहन एवं अभिषेक कुमार की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाया। सभी अतिथियों ने युवाओं को अपने कौशल को निरंतर निखारने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

इस कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पेशेवर दक्षताओं से सशक्त बनाना, उन्हें सार्थक रोजगार के लिए तैयार करना और स्वरोजगार के अवसरों की ओर प्रेरित करना है। कुशल युवाओं के निर्माण के माध्यम से यह पहल देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आईजीएल द्वारा दिया गया यह सहयोग समाज के वंचित और जरूरतमंद युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। ■

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पेशेवर दक्षताओं से सशक्त बनाना, उन्हें सार्थक रोजगार के लिए तैयार करना और स्वरोजगार के अवसरों की ओर प्रेरित करना है। कुशल युवाओं के निर्माण के माध्यम से यह पहल देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

विलक्षण वैभव सूर्यवंशी

वैभव दुनिया के किसी भी गेंदबाज से खौफ नहीं खाते हैं। उनका मंत्र है- डर के आगे जीत है। चाहे क्रिकेट हो या युद्ध का मैदान, किसी योद्धा के दिल से जब प्रतिद्वंद्वी या शत्रु का खौफ निकल जाता है तो वह जग जीत लेता है। इसी को मैदान पर भारत का 14 बरस का क्रिकेट का 'अभिमन्यु' सच साबित कर रहा है।

सत्येन्द्र पाल सिंह

भारत के 14 बरस के वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का 'सूर्य' उनके नाम के अनुरूप दुनिया में चमक रहा है। उन्होंने बल्ले के धमाल से देश और दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को अपना मुरीद बना लिया। उनकी बल्लेबाजी की गूंज आज ठीक उसी तरह दुनिया भर में सुनाई दे रही है जैसी क्रिकेट के हर फॉर्मेट के सर्वकालीन महानतम बल्लेबाज सचिन तेंडुलकर की मात्र 15 बरस की उम्र में सुनी गई थी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की ताकत है उनका खुद पर भरोसा। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव ताजपुर के बाशिंदे वैभव को बल्लेबाजी करता देख हर कोई बरबस यही कहता है- विलक्षण। वह बेशक क्रिकेट के भविष्य के सुपर स्टार हैं, लेकिन वह भी भारत के हर क्रिकेट प्रेमियों की तरह सचिन तेंडुलकर और विराट कोहली की बल्लेबाजी के मुरीद हैं। वैभव दुनिया के किसी भी गेंदबाज से खौफ नहीं खाते हैं। उनका मंत्र है- डर के आगे जीत है। चाहे क्रिकेट हो या युद्ध का मैदान, किसी योद्धा के दिल से जब प्रतिद्वंद्वी या शत्रु का खौफ निकल जाता है तो वह जग जीत लेता है। इसी को मैदान पर भारत का 14 बरस का क्रिकेट का 'अभिमन्यु' सच साबित कर रहा है।

वैभव सूर्यवंशी को 26 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्रिकेट में एक अलग मुकाम की ओर बढ़ने के सफर में उनके किसान पिता और पहले क्रिकेट उस्ताद संजीव सूर्यवंशी का जुनून अहम है। उन्होंने भी भारत के लिए खेलने का सपना संजोया था, जो पूरा नहीं हो पाया। अपने पिता के अधूरे सपने को वैभव ने पहले बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी व फिर वन डे विजय हजारे ट्रॉफी और भारत की अंडर 19 टीम के लिए खेल पूरा किया।

मैदान के बाहर भी उनकी लोकप्रियता उनके प्रदर्शन के अनुरूप रही। वह 2024 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए भारतीय और दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वालों में छठे स्थान पर रहे। इंस्टाग्राम ने भी अपने आधिकारिक पेज पर उनके क्रिकेट सफर को विशेष रूप से दिखाया। विराट कोहली के बाद यह सम्मान पाने वाले वह दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने। वैभव ने अपनी कप्तानी में दूसरे मैच में तूफानी अर्द्धशतक और तीसरे में तूफानी शतक से भारत को मेजबान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे अंतरराष्ट्रीय यूथ अंडर 19

> **वैभव के पास शानदार बैट स्पीड है। हाथ व आंखों के बेहतरीन तालमेल के साथ उनकी हाई बैकलिफ्ट उन्हें गेंद की लेंग्थ को बेहतर ढंग से परखने का पूरा मौका देती है। वह किसी भी शॉर्ट या बहुत फुल गेंद को तुरंत पहचान लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। हम उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहते। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि वह इसे सरल रखे और अपने क्रिकेट का आनंद ले। हम चाहते हैं कि वह भ्रमित हुए बिना बेफिक्र हो अपनी क्रिकेट खेले।**
>
> **राहुल द्रविड़**
> **राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कोच**

मैचों की क्रिकेट सीरीज 3-0 जिता दर्शाया कि वह जिम्बाब्वे और नामिबिया में 15 जनवरी से शुरू आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का सबसे बड़ा आकर्षण रहने वाले हैं। स्विंग और अपने दोनों पैर जमीन पर टिकाए रख कर शॉट खेलने की कूवत के चलते उनकी बल्लेबाजी की तुलना अभी से शिखर धवन से की जाने लगी है। वैभव के स्क्वॉयर ड्राइव, कवर ड्राइव और खासतौर पर डीप मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट उनके बल्लेबाजी कौशल और बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हैं। उनकी बल्लेबाजी शेयर बाजार के 'ज्यादा जोखिम, ज्यादा लाभ' के सिद्धांत पर चलती है। वह जितनी तेज रफ्तार से खेलते हैं उसमें आउट होने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। बावजूद इसके, वैभव सूर्यवंशी जैसे नैसर्गिक बल्लेबाज को किसी भी क्रिकेट उस्ताद से उनकी बल्लेबाजी की आक्रामक शैली से छेड़छाड़ करने की बजाय कुछ सुझाव मिलने भर की जरूरत है। जब-जब सूर्यवंशी का बल्ला बोलेगा, उनकी बल्लेबाजी का 'वैभव' चारों ओर तो बढ़ेगा ही, भारत की शान भी बढ़ेगी। उनकी बल्लेबाजी दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक युवराज सिंह और अपनी दे दनादन अंदाज से बल्लेबाजी में विख्यात रहे वीरेंद्र सहवाग के विस्फोटक तेवरों का आदर्श मिश्रण नजर आती है। वैभव भी युवराज और सहवाग की तरह अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में धूम मचा भारत की सीनियर टीम के लिए खेलने का सपना संजोए हैं। बहुत जल्द ही वह भारत की सीनियर टीम में सबसे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभिषेक शर्मा के साथ खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। युवराज और सहवाग की तरह वैभव का बल्लेबाजी दर्शन भी है- गेंद यदि उनके पाले में है तो उस पर भरपूर प्रहार कर रन बनाना। इन दोनों की तरह उन्हें भी 'छक्के' जड़ना बहुत भाता है। फिलहाल वह केवल छक्कों और चौकों से रन बनाने में यकीन करते हैं।

वैभव ने भारत के लिए मात्र 13 बरस की उम्र में अंडर 19 क्रिकेट करियर का आगाज शतक के साथ किया। जबकि आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स ने मात्र 13 बरस की उम्र में उन्हें एक करोड़ दस लाख रुपये में खरीदा है। आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले वह सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बनने के साथ इसके इतिहास में मात्र 35 गेंदों में क्रिस गेल (30 गेंद) के बाद दूसरे सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं। इससे पहले वह ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ 58 गेंदों पर चार दिनी मैच में शतक जड़ चुके थे। उन्होंने दिखा दिया कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में उन्हें रोकना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। अंडर 19 एशिया कप में उन्होंने 182 की स्ट्राइक रेट और 50 रन से ज्यादा की औसत से 262 रन बनाए। इसमें उन्होंने 95 गेंदों पर अपनी 171 रन की पारी के दौरान यूथ वन डे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का भी रिकॉर्ड बना दिया।

वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च, 2011 को ताजपुर में हुआ। उन्होंने मात्र चार बरस की उम्र में ही बल्ला थाम लिया। क्रिकेट का ककहरा उन्होंने अपने पिता से ही सीखा। जब वह आठ बरस के हुए तो उनके पिता संजीव ने उनका दाखिला क्रिकेट कोच मनीष ओझा की पटना स्थित जेननेक्स एकेडमी में करा दिया। वैभव के पिता उन्हें एक दिन छोड़ कर हर दूसरे दिन क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए समस्तीपुर से पटना एकेडमी में ले जाते थे। बेटे के क्रिकेट जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तो बेची ही, नौकरी तक छोड़ दी। शुरू में उनके पिता ने घर में ही क्रिकेट नेट लगा दिया। वैभव के बचपन के कोच मनीष ओझा कहते हैं कि वह बहुत जल्द बहुत कुछ सीखते हैं और दुनिया के महानतम बल्लेबाज ब्रायन लारा के मुरीद हैं। वैभव की असल उम्र को लेकर कुछ सवाल उठे थे। विवाद चाहे जो भी हो, लेकिन वह उस लिहाज से भी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व बल्लेबाज हैं।

वह जितनी जल्दी कामयाबियों की सीढ़ी चढ़ेंगे, उतना ज्यादा ही दुनिया भर के क्रिकेट उस्ताद उन्हें रोकने की रणनीति बनाने में जुट जाएंगे। इससे बेशक उनकी राह मुश्किल होगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं उनमें इस तरह की सब बाधाओं को लांघ कर अपनी मंजिल पर पहुंचने की कूवत है।■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

दिल्ली-एनसीआर में शुरू हुई भारत टैक्सी

युवा सहकार टीम

सहकारिता के माध्यम से देश के परिवहन क्षेत्र की तस्वीर बदलने के उद्देश्य से मोबाइल ऐप आधारित कैब सर्विस भारत टैक्सी का दिल्ली-एनसीआर में परिचालन शुरू हो गया है। पहली जनवरी से इस टैक्सी सेवा के शुरू होने से न केवल यात्रियों को नया विकल्प मिला है, बल्कि ड्राइवरों को सशक्त बनाकर सहकारी उद्यमिता को बढ़ावा देने और सहकारिता क्षेत्र का विस्तार करने में भी यह मददगार साबित होगा। भारत टैक्सी ऐप से यात्री टैक्सी, बाइक, ऑटो बुक कर सकते हैं। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे देश के अन्य महानगरों में भी इसी साल इस सेवा के शुरू होने की उम्मीद है। भारत टैक्सी का ट्रायल पिछले साल नवंबर में दिल्ली और गुजरात के राजकोट में शुरू हुआ था, जो सफल रहा।

भारत टैक्सी में किराया फिक्स्ड रखा गया है और कोई 'सर्ज प्राइसिंग' नहीं है। इसका मतलब है कि भीड़भाड़ वाले समय या बारिश होने पर किराया अचानक नहीं बढ़ेगा। यह सेवा अचानक 'राइड कैंसिल' होने जैसी समस्याओं को कम करने की कोशिश कर रही है, जो निजी कंपनियों के साथ एक आम शिकायत बन गई है। साथ ही इसके ड्राइवरों को बिना कमीशन के पूरा किराया मिलेगा। अभी ओला, उबर जैसी कैब सर्विस कंपनियां ड्राइवरों की कमाई में से 20-30 प्रतिशत तक कमीशन काटती हैं। जबकि भारत टैक्सी एक दिन के सिर्फ 30 रुपये बतौर कमीशन लेती है। प्राइवेट कंपनियां ड्राइवरों को लाभ में भागीदार नहीं बनातीं, जबकि भारत टैक्सी में ड्राइवर इसका परिचालन करने वाली सहकारी समिति सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड में शेयरधारक होंगे और उनके पास भी मालिकाना हक होगा। हर ड्राइवर को एक शेयर लेना ही है। वह अधिकतम 5 शेयर ले सकते हैं।

> **मुंबई, बेंगलुरु जैसे अन्य शहरों में जल्दी होगी इसकी शुरुआत, सहकारिता आधारित कैब सर्विस से बदलेगी देश के परिवहन क्षेत्र की तस्वीर**

सुरक्षा के लिहाज से भारत टैक्सी में ड्राइवरों का वेरिफिकेशन किया गया है और इसे दिल्ली पुलिस व अन्य सरकारी एजेंसियों के सिस्टम से जोड़ा गया है, ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। डिजी-लॉकर और उमंग ऐप के साथ जुड़ाव के जरिये ड्राइवरों की सही पहचान, रियल-टाइम ट्रैकिंग और नियमित ऑडिट सुनिश्चित गई है।

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत रजिस्ट्रेशन कराया गया है। देशभर की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने वाली राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) इस सहकारी समिति की मुख्य प्रमोटर है, जबकि देश की प्रमुख सहकारी संस्थाएं अमूल, नेफेड, नाबार्ड, इफको, कृभको, एनडीडीबी और एनसीईएल अन्य प्रमोटर हैं। देश की दिग्गज सहकारी संस्थाओं का समर्थन मिलने से सहकार टैक्सी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भारत टैक्सी से दिल्ली-एनसीआर में अब तक 3 लाख से ज्यादा ग्राहक और 1.50 लाख ड्राइवर जुड़ चुके हैं। अभी रोजाना 50 हजार से ज्यादा राइड इसके ऐप से बुक हो रही है। यह ऐप दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन सेवा से सीधे जुड़ा है। इससे मुश्किल में पुलिस की तुरंत सहायता मिल जाती है। भारत टैक्सी सर्विस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किशन पाटनी के अनुसार, दिल्ली में कुल 10 लाख ड्राइवर हैं, जिनमें 4.5 लाख कैब, 3.5 लाख ऑटो और 2 लाख बाइक चलाते हैं। भारत टैक्सी का मकसद ड्राइवरों को प्राइवेट ऐप आधारित टैक्सी के मकड़जाल से बाहर निकालना और एल्गोरिदम की गुलामी से मुक्ति दिलाना है। सहकारिता का टैक्सी मॉडल भारत में नए अमूल के प्रयोग की ओर प्रोत्साहित करता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की भागीदारी इस पूरी योजना को सहकारी मदद और सरकारी योजनाओं से जोड़कर विश्वसनीयता देने का काम करेगी।

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

IFFCO KISAN DRONE

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

इफको नैनो उर्वरक अपनाएं
अधिक उपज और गुणवत्ता पाएं
इफको की असरदार जोड़ी

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री न. 1800-103-1967
www.iffco.in | www.nanourea.in I www.nanodap.in

National Yuva Co-operative Society Limited

NYCS

Empowering Financial Independence

Our Services

Loans: Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.

Deposits: Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.

Simplified Process: Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

Our Reach

- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

Why Choose NYCS Ltd.?

- **Trusted Expertise** – Over 20 years in financial services.
- **Nationwide Presence** – A rapidly growing network.
- **Member-Focused** – Tailored financial solutions.
- **Youth Empowerment** – Supporting young entrepreneurs.

Contact Us

209, 2nd Floor, A2B,
Vardhman Janak Market,
Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsltd.com

Together, let's build a brighter financial future!